पृथ्वी नाथ राम

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

24 अगस्त, 2004

[अरिजीत पसायत और डी. एम. धर्माधिकारी, न्यायमूर्तिगण]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971:

धाराएँ 11 और 15 - अवमानना क्षेत्राधिकार - दायरा - उच्च न्यायालय के आदेश का गैर-अनुपालन - पीड़ित पक्ष अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दायर करता है - न्यायालय आदेश की शुद्धता की जांच करता है और अवमानना के लिए कार्रवाई करने से इनकार करता है - माना गया, अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय उस आदेश से परे नहीं जा सकता जिसके गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है - यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 215 - प्रथा और प्रक्रिया।

उच्च न्यायालय के एक आदेश के गैर-अनुपालन के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने के एक आवेदन में, एक एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश की शुद्धता की जांच करने के लिए आगे बढ़े और माना कि उसमें दिए गए निर्देश नहीं दिए जा सकते थे और, इसलिए, अवमानना के लिए कोई कार्रवाई करने की गुंजाइश नहीं थी। व्यथित होकर, आवेदक ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार्य करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजते हुए, न्यायालय ने:

अभिनिर्धारित किया: 1.1. अवमानना के लिए एक आवेदन से निपटते समय, न्यायालय मुख्य रूप से इस प्रश्न से संबंधित होता है कि क्या पहले के निर्णय, जिसे उसकी

अंतिम रूप मिल चुका है, का पालन किया गया है या नहीं और क्या उस पक्ष का आचरण, जिस पर निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप लगाया गया है, अवमानना पूर्ण है। न्यायालय के लिए पहले के निर्णय की शुद्धता की जांच करना, जिसे चुनौती नहीं दी गई है, और पहले के निर्णय से अलग दृष्टिकोण अपनाना अनुमेय नहीं होगा। न्यायालय उस आदेश से परे नहीं जा सकता है, जिसके गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है। यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता है या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता है या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता है। यह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन से निपटते समय समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने जैसा होगा। वही अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा। [742-जी-एच; 743-ए-सी; 744-सी-डी]

के.जी. डेसारी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2001) 10 एससीसी 496 और *मोहम्मद इकबाल खंडय बनाम अब्दुल मजीद राथर,* एआईआर (1994) एससी 2252, पर अवलंबन किया गया।

टी.आर. धनंजया बनाम जे. वासुदेवन, (1995] 5 एससीसी 619, को संदर्भित किया गया।

नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1994] 6 एससीसी 352, को अनुपयुक्त माना गया।

1.2. यदि कोई संबंधित पक्ष आदेश से व्यथित है, जो उसकी राय में गलत है या नियमों के विरुद्ध है, या इसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया था या अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। साथ ही, एक दिए गए मामले में, भले ही अंततः अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है या मुख्य कार्यवाही में एक पक्ष को राहत नहीं दी जाती है, इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवज्ञा के लिए आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। (744-ए-बी, इ-एफ)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2000 की दीवानी अपील सं. 5024

1999 की एम.जे.सी. सं. 262 में, पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 7.3.2000 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2004 की आई.ए. सं. 10-11

अपीलकर्ता के लिए: राजू रामचंद्रन, ज़ैकी अहमद खान और इरशाद अहमद।

उत्तरदाता के लिए: बी.बी. सिंह।

झारखंड राज्य के लिए: अनिल कुमार झा।

उत्तरदाता के लिए: लक्ष्मी रमन सिंह।

बी.पी.एस.सी. के लिए: अनुराग शर्मा और नवीन प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय

अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया: अपीलकर्ता ने भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 215 के साथ पठित अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 और 15 के तहत एक आवेदन दायर किया। ऐसे आवेदन का आधार, 1998 की सीडब्लूजेसी 1120 में पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.3.1999 के आदेश से दिए गए निर्देशों का कथित तौर पर पालन न करना था।

उक्त उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने, अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन से निपटते हुए, यह मानते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है कि अवमानना के लिए कोई कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गौर किया कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन से निपटते समय विचार का दायरा इस प्रश्न तक सीमित था कि आदेश का अनुपालन किया गया था या नहीं, फिर भी आदेश की शुद्धता की जांच करने के लिए आगे बढ़े और पक्षकारों को उन्हें

संतुष्ट करने के लिए बुलाया कि दिनांक 30.3.1999 के आदेश में दिए गए निर्देशों जैसा निर्देश जारी किया जा सकता था। गहन विश्लेषण के बाद, उन्होंने यह माना कि निर्देश नहीं दिए जा सकते थे और इसलिए अवमानना के लिए कोई कार्रवाई करने की गुंजाइश नहीं थी।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने अवमानना आवेदन पर विचार करते समय कानून के सही मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा है। संक्षेप में, उन्होंने एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया है। अवमानना कार्यवाही में यह जांच करना संभव नहीं है कि जिस आदेश के कार्यान्वयन न होने का तर्क दिया जा रहा है, वह वैध है या नहीं। यह विचारणीय विषय नहीं है।

जवाब में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि ऐसे मामलों में कोई पूर्वनिर्धारित सूत्र नहीं किया जा सकता है। यदि आदेश लागू करने योग्य नहीं था, तो निश्चित रूप से अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आवेदन से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए यह विचार करना खुला था कि आदेश कानूनी था या नहीं।

अवमानना के लिए एक आवेदन से निपटते समय, न्यायालय वास्तव में इस प्रश्न से संबंधित होता है कि क्या पहले के निर्णय, जिसे उसकी अंतिम रूप मिल चुका है, का पालन किया गया था या नहीं। न्यायालय के लिए पहले के निर्णय की शुद्धता की जांच करना अनुमेय नहीं होगा जिसे चुनौती नहीं दी गई थी और पहले के निर्णय से अलग दृष्टिकोण अपनाना। *के.जी. डेसारी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*, [2001] 10 एससीसी 496 में भी इसी तरह का विचार लिया गया था। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से उस पक्ष के अवमाननापूर्ण आचरण के प्रश्न से संबंधित होता है जिस पर निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप लगाया गया है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी, तो संबंधित पक्ष के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करना है यदि उसके अनुसार वही कानूनी रूप से संधारणीय

नहीं है। इस तरह के प्रश्न को आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मूल कार्यवाही पर उस तरीके से निर्णय लेने की शक्ति अपने ऊपर नहीं ले सकता है जिस तरीके से निर्णय या आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा निपटा नहीं गया था। हालांकि बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा *नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,* [1994] 6 एससीसी 352 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था, हम पाते हैं कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उस मामले में आदेश का पालन करने की असंभवता के बारे में प्रश्न उठा था। यदि राज्य का वह रुख था, तो कम से कम वह यह कर सकता था कि उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय की शुद्धता को चुनौती देता। राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से विपरीत रुख अपनाया। एक यह था कि विशेष रूप से कुछ भी करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं था और, दूसरा यह था कि जो कुछ किया जाना आवश्यक था वह किया जा चुका है। यदि जो कुछ किया जाना था वह किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आदेशों को पूरा करना असंभव था। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि पहले दिए गए निर्देश को पूरा करना असंभव था या दिए गए निर्देश का पालन किया गया है।

निर्देश का पालन करने की असंभवता के प्रश्न पर, *टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन,* [1995] 5 एससीसी 619 में व्यक्त विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें यह माना गया था कि जब दावे पर आपसी निर्णय हो चुका है और वह अंतिम रूप ले चुका है, तो उत्तरदाता के लिए आदेशों के पीछे जाकर और नियमों का सहारा लेकर परिणाम को पलटने या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को गतिरोध उत्पन्न करने के लिए कानूनी बहाना बनाने का प्रयास करना उचित नहीं है।

मोहम्मद इकबाल खंडय बनाम अब्दुल मजीद राथर, एआईआर (1994) एससी

2252 में, यह माना गया था कि यदि कोई पक्ष आदेश से व्यथित है, तो उसे अपीलीय कार्यवाही शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और आदेश की उपेक्षा नहीं कर सकता है और अवमानना कार्यवाही शुरू होने के समय कार्यान्वयन की कठिनाइयों के बारे में तर्क नहीं दे सकता है।

यदि कोई संबंधित पक्ष आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत है या नियमों के विरुद्ध है या इसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया था या अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। अवमानना कार्यवाही में आदेश की सहीता या गलतता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। सही हो या गलत, आदेश का पालन किया जाना है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पक्ष अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। अवमानना के लिए आवेदन से निपटते समय न्यायालय उस आदेश से परे नहीं जा सकता है जिसके गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। यह आदेश से परे नहीं जा सकता। यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता है या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता है या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता है। यह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन से निपटते समय समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने जैसा होगा। वही अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है। इसे कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में आवेदन से निपटना चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता या अन्यथा के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

एक मामले में, भले ही अंततः अंतरिम आदेश रद्द कर दिया जाता है या मुख्य कार्यवाही में एक पक्ष को राहत नहीं दी जाती है, दूसरा पक्ष न्यायालय द्वारा पारित किसी भी

अंतरिम आदेश की अवज्ञा के लिए उसे आधार के रूप में नहीं ले सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद, विवाद वर्तमान में झारखंड राज्य से संबंधित है, जिसे मूल उत्तरदाता, बिहार राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

अपील को उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आर. पी. अपील स्वीकार किया जाता है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।